भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ

विधानमंडलों को डिजिटल विधानमंडलों में परिवर्तित करने में तेज़ी लाने के लिए राज्यों ने "नेवा पर नई दिल्ली प्रस्ताव 2025" को अपनाया

संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। सम्मेलन में "एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन" के दृष्टिकोण के तहत पूरे देश में डिजिटल और कागज-रहित विधायी कार्यचालन को सुदृढ़ करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की गई।

सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू द्वारा किया गया। सम्मेलन में राज्यों के विधानमंडलों और नोडल विभागों के सचिवों सहित 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

<u>अध्यक्षीय भाषण</u>

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने अपने भाषण में राज्यों द्वारा मिलकर किए गए प्रयासों की सराहना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि नेवा हमारे लोकतंत्र की आत्मा बन चुका है, जिससे संसदीय लोकतंत्र की मज़बूती ओर भी बढ़ गई है।

.....2/-

संसदीय कार्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन ने अपने समापन भाषण में कहा कि नेवा सभी राज्यों के विधानमंडलों के लिए एक साझा विधायी मंच उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री निकुंज बिहारी धल ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में, राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की सामूहिक सफलता पर प्रकाश डाला और बताया कि नेवा के माध्यम से 90,000 से ज़्यादा प्रश्नों और 600 विधेयकों पर कार्रवाई की गई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में अपर सचिव और नेवा के मिशन लीडर, डॉ. सत्य प्रकाश ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि विधानमंडल 'विकसित भारत' की नींव का काम करेंगे, जबकि नेवा इस विज़न को आगे बढ़ाने वाले डिजिटल इनेबलर के तौर पर काम करेगा। उन्होंने राज्यों से कैपेसिटी-बिल्डिंग, डिजिटल वर्कफ़्लो और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप के ज़रिए रफ़्तार बनाए रखने की अपील की।

.....3/-

सभी राज्यों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें अपनाए गए सबसे अच्छे तरीकों, डिजिटलीकरण की ओर उनके सफ़र में आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया और नेवा इकोसिस्टम को भविष्य में बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए गए।

नेवा पर नई दिल्ली प्रस्ताव 2025 की स्वीकृति

प्रतिनिधियों ने नेवा पर नई दिल्ली प्रस्ताव 2025 को एकमत से स्वीकृत किया, जिसमें नेवा के त्वरित कार्यान्वयन और डिजिटल गवर्नेंस में कोऑपरेटिव फ़ेडरलिज़्म को मज़बूत करने के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की गई।

प्रस्ताव में निम्नलिखित महत्वूपर्ण बातें शामिल हैं:

- सचिवों की समिति बनाना
- नेवा को त्वरित रूप से पूर्णत: लागू करना
- कैपेसिटी बिल्डिंग को मज़बूत करना
- पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज और अपलोड करना
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना
- एक राष्ट्रीय विधायी डिजिटल इंडेक्स की खोज।

…..4/-

आज तक, 28 विधायी सदन नेवा के कार्यान्वयन हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और 20 सदन नेवा के माध्यम से लाइव हैं, जो डिजिटल विधानमंडल की दिशा में देश की लगातार प्रगति को दर्शाता है।

सम्मेलन का समापन संसदीय कार्य राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरूगन द्वारा नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव राज्यों को 'सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑनर' तथा सम्मेलन में सक्रिय प्रतिभागिता हेतु सभी प्रतिनिधियों को 'सर्टिफिकेट ऑफ़ एप्रिसिएशन' प्रदान करने के साथ हुआ।

मंत्रालय ने राज्यों के विधानमंडलों को सभी ज़रूरी मदद देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि नेवा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाई जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जा सके और नेवा को एक संयुक्त, सुरक्षित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित डिजिटल विधायी प्लेटफॉर्म के तौर पर और मज़बूत किया जा सके।

****